दिसम्बर, 1969 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिनको दूकानों के आरक्षण के आधार पर उन दूकानों का आवंटन किया गया था; और

(घ) अनुसूचित जातियों के उन आवेदन कर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है जिनके आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये गये थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) :(क): जी, हाँ।

(ख) और (घ). 29 दूकानों में से 4 अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों को आवंटन करने के लिए सुरक्षित की गई हैं। 4 में से एक दुकान, अनुसूचित जाति के एक संसद सदस्य की विधवा को आवंटित की जानी है। शेष 3 दूकानें अनुसूचित जाति समुदाय के उन सदस्यों को दी जानी हैं, जो सार्वजनिक भूमि पर अनधिवासी हैं और गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत वैकल्पिक वास के आवंटन के पात्र हैं। इस उद्देश्य से दिसम्बर 1969 में दिल्ली प्रशासन ने एक विज्ञापन जारी किया था, जिसके उत्तर में 21 आवेदन प्राप्त हुए थे। जाँच करने पर उन में से कोई भी गाडगिल आश्वासन के अन्तर्गत पात्र नहीं पाया गया।

(ग) अभी तक अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों अथवा अन्य लोगों को दूकान का कोई आवंटन नहीं किया गया।

गोरखपुर उर्वरक कारखाने के कारखाना इंजीनियरिंग (इलेक्ट्रिकल) विभाग में कथित भ्रष्टाचार

6179. श्री मोलहू प्रसाद : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक कारखाना कर्मचारी संघ, गोरखपुर के मंत्री ने 13 जनवरी, 1970 को भारतीय उर्वरक निगम गोरखपुर के महाप्रबंधक और उसके प्रबन्धक को गोरखपुर उर्वरक कारखाने के कारखाना इंजीनियरिंग (इलैक्ट्रिकल) विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा कदाचार के बारे में शिकायतें भेजी हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर संबन्धित अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या इस कार्मिक संघ के मंत्री ने 9 मार्च, 1970 को इस आशय की शिकायत उन को भेजी थी ; और

(घ) यदि हाँ, तो उनके द्वारा इस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण): (क) जी हाँ। उर्वरक कारखाना मजदूर संघ, गोरखपुर का भारतीय उर्वरक निगम के चेयरमैन तथा प्रबन्ध निर्देशक के नाम दिनांक 13-2-70 का एक पत्र, जिस में बिना किसी विशिष्ट उदाहरण के, गोरखपुर कारखाने के संयंत्र इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के एक अफसर के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे, निगम को प्राप्त हुआ था।

(ख) क्योंकि लगाये गये आरोप अस्पष्ट हैं, निगम ने सम्बन्धित अफसर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। तथापि, निगम के मुख्यालय ने गोरखपुर के महा प्रबन्धक से अफसर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि में संघ से विशिष्ट उदाहरण या तथ्यों का पता लगाने का अनुरोध किया है।

(ग) जी हाँ।

(घ) शिकायत निगम को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी गई।

BLINDNESS COSTING RS. 10,000 CRORES TO THE COUNTRY

6180. Shri R. K. Birla : Will the Minister of **Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the attention of the Union Government has been drawn to a news report appearing in the 'Hindustan Times'